भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 1002
गुरुवार, 5 फ़रवरी, 2026/16 माघ, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

प्रमुख महानगरीय विमानपत्तनों पर क्षमता संबंधी बाधाएं

1002. श्री प्रवीन खंडेलवालः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्रमुख महानगरीय विमानपत्तनों पर यात्रियों की तीव्र वृद्धि के कारण विशेषकर व्यस्ततम समय के दौरान उत्पन्न होने वाली क्षमता संबंधी बाधाओं का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्रयोक्ता प्रभारों में वृद्धि किए बिना स्लॉट अनुकूलन, क्षेत्रीय संपर्क और यात्री अनुभव में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) : वर्तमान में, छह महानगरीय शहरों नामतः दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु को सेवा प्रदान करने वाले हवाईअड्डों पर क्षमता संबंधी कोई बाधा नहीं है।

(ख) : नागर विमानन मंत्रालय ने स्लॉट के उचित और पारदर्शी वितरण के लिए स्लॉट आवंटन हेतु दिशानिर्देश तैयार किए हैं। तदनुसार, हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा एयरलाइनों को ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अनुसूचियों के लिए स्लॉट आवंटित करने हेतु स्लॉट आवंटन समिति की बैठकें वर्ष में दो बार आयोजित की जाती हैं। ये अनुसूचियां नागर विमानन महानिदेशालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। चूंकि स्लॉट आवंटन एक नियमित प्रक्रिया है जो वर्ष में दो बार समिति की बैठकों के आधार पर आयोजित की जाती है, इसलिए आगामी बैठकों में अनुसूची के किसी भी अप्रयुक्त स्लॉट की समीक्षा/समायोजन किया जाता है और इच्छुक एयरलाइनों को इनका आवंटन किया जाता है।

सरकार ने अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान करने के लिए देशभर में 120 नए गंतव्यों के लिए क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने हेतु संशोधित 'उड़ान' योजना को आरंभ करने की घोषणा की है।

इसके अलावा, यात्री अनुभव को बढ़ाने के लिए, हवाईअड्डा प्रचालक प्रौद्योगिकी अद्यतन सहित टर्मिनल भवनों का उन्नयन और विस्तार करते हैं। स्वतंत्र आर्थिक विनियामक अर्थात भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (एईआरए), उचित प्रयोक्ता प्रभार सुनिश्चित करने के लिए उन प्रमुख हवाईअड्डों के हवाईअड्डा टैरिफ का निर्धारण करते समय इस प्रकार के उन्नयन/विस्तार हेतु प्रमुख हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय की समीक्षा करता है।

******